



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10, 1941

No. 443]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सं. 29/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 549(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 276 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

No. 29/2019-Customs (ADD)

G.S.R.549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2018-Customs (ADD), dated the 23rd March 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 276 (E), dated the 23rd March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/211/2016-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सं.30/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.550(अ).—जब कि बंगलादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “जूट उत्पाद” जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;
- (ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;
- (iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;
- (iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जब कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क लगाया था;

और जब कि मैसर्स नेचुरल जूट मिल्स लि. (उत्पादक/निर्यातक) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/व्यापारी) (बंगलादेश) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/9/2017-डीजीएडी, दिनांक 18 जनवरी, 2018 जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए, जिसे सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 16/2018 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से, जिसे सा.का.नि. 276 (अ.), 23 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचित किया गया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/10/2017- डीजीएडी, दिनांक 2 मई, 2019 में अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे दिनांक 2 मई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मैसर्स नेचुरल जूट मिल्स (उत्पादक/निर्यातक) [बंगलादेश] ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विषयगत माल के कुल निर्यात का 1% भी निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार यह निर्यात इतना कम है कि आवेदन करने वाले उत्पादक/निर्यातक को अलग से डंपिंग मार्जिन देने के उद्देश्य से इसको वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व मात्रा नहीं माना जा सकता है और इसीलिए उन्होंने यह सिफारिश की है कि इस उत्पादक/निर्यातक का आंकलन अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क

(एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था की शुल्क सारणी की अवशिष्ट श्रेणी के अनुसार किया जाता रहेगा।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारत सरकार, में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी 2017 की अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), संख्या सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के तहत निम्नलिखित और आगे भी संशोधन, एतद्वारा, करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लिमिटेड (उत्पादक), मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर), नेचुरल जूट मिल्स (उत्पादक/निर्यातक) [बंगलादेश] और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) [बंगलादेश] के द्वारा किए जाने वाले विषयगत माल के निर्यात का अंतिम आंकलन उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत किया जाएगा"

[फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी, 2017 को सा.का.नि. संख्या 11(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 32 (अ.) दिनांक 15 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

No. 30/2019-Customs (ADD)

G.S.R.550(E).—Whereas, in the matter of import of 'Jute Products' namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority, in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I vide notification No. 14/19/2015-DGAD, dated the 20th October, 2016, had come to the conclusion that-

- (i) there is dumping of subject goods from the subject countries;
- (ii) imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry;
- (iii) performance of domestic industry has deteriorated in the terms of profitability return on investments and cash flow;
- (iv) injury to domestic industry has been caused by dumped imports,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 11(E) dated the 5th January, 2017;

And whereas, M/s. Natural Jute Mill (Producer/Exporter) [Bangladesh] and M/s Kreation Global, LLC, USA (Exporter/ Trader) [Bangladesh] had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No. 7/9/2017-DGAD, dated 18th January 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 18th January, 2018, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above mentioned parties till the completion of the review by it, which was notified vide enabling Customs notification No. 16/2018-Customs (ADD), dated the 23rd March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 276(E), dated the 23rd March, 2018;

And whereas, the designated authority, vide its final findings in notification No. 7/09/2017-DGAD, dated the 2nd May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 2nd May, 2019, has come to the conclusion that M/s. Natural Jute Mill (Producer/Exporter) [Bangladesh] has not even exported 1% of the total exports of the subject goods to India during the period of investigation, which is too insignificant to be considered as commercially representative quantity to be adopted for according individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter and therefore recommended that the producer/exporter would continue to be assessed as per residual category of duty table of the notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 11(E) dated the 5th January, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th of January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 5th of January, 2017, namely:-

In the said notification, for the Explanation, the following shall be substituted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this notification, the exports of subject goods by M/s. Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer), M/s. IB Jute Corporation (Exporter/ Trader), M/s. Natural Jute Mill (Producer/Exporter) [Bangladesh] and M/s. Kreation Global, LLC, USA (Exporter/ Trader) [Bangladesh] shall be finally assessed under the residual categories specified in the above Table.”.

[F. No. 354/211/2016-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017 and was last amended by notification No. 03/2019-Customs (ADD), dated the 15th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 32 (E), dated the 15th January, 2019.